

राजनाथ का कमांडरों को निर्देश, युद्ध में दुश्मन को रणनीति से चौंकाएं

रक्षा मंत्री का सेना को किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहने का आह्वान

संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में एआइ, सुरक्षित संचार नेटवर्क पर दिया जोर

नई दिल्ली, 9 मई: रक्षा मंत्री राजनथ सिंह ने तीनों सेवाओं के शीर्ष सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया कि वे आधुनिक युद्ध में "आश्चर्य का तत्व" शामिल करें ताकि भारत के विशेषियों को पता हो जा सके और रणनीति स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा, "भविष्य के युद्ध केवल हथियारों के माध्यम से नहीं जीते जायेंगे, बल्कि नई सोच और बढ़ते हुए आतंकी सहयोग से जीते जायेंगे।"



रक्षा मंत्री राजनथ सिंह युवावर्ग को जनपूर में आपत्काल सिद्ध हो फलने परभाट के मीक पर आयोजित कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए। (ए.ए.ए.)

संयुक्त कमांडरों को "आश्चर्य का तत्व" विकसित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे राष्ट्र के विशेषियों के लिए अप्रत्याशित बने रहें और किसी भी स्थिति में रणनीतिक बतल हासिल कर सकें। हालांकि, उन्होंने उन्हें दुश्मन के आश्चर्य के तत्व के प्रति सतर्क रहने और हमला दे कर अपेक्षाएं पर जोर दिया। राजनथ सिंह ने कमांडरों से कहा कि वे आपत्काल और ज्वलमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य से संयुक्त "भविष्य के लिए तैयार" रहें। उन्होंने तेजी से विकसित हो रहे रू-रणनीतिक

सुरक्षा परिदृश्य में तैयार रहने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वयंचालित प्रणालियाँ, डाटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क में क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्षों को हाइब्रिड खतरों, सूचना प्रभुत्व और सहाय, अंतरिक्ष, विद्युतयुद्ध और संगठनात्मक छापे में एक साथ विभिन्न गुप्त संचालन द्वारा आकार दिया जाएगा।

दिल्ली सहित 23 राज्यों में जल्द एसआइआर की होगी शुरुआत

आयोग ब्यू, नई दिल्ली

बंगलूर, केरल सहित पांच राज्यों के विस आयोग से नियुक्त के बाद चुनाव आयोग अब दिल्ली, पंजाब सहित बाकी बचे 23 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष स्थान पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम जल्द ही शुरू करेगा। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक इसकी घोषणा हो जाएगी। पहले इसे अंग्रेज से शुरू करने की तैयारी थी, पर बंगलूर चुनाव को लेकर बढ़ती व्यस्तता के मद्देनظر आयोग ने इसे चुनाव बाद शुरू करने के संकेत दिए थे।

इस बीच आयोग ने चुनाव से निपटने के बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होने वाले एसआइआर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने इसे लेकर 19 फरवरी 2026 को ही इन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एसआइआर से जुड़ी तैयारी करने में निर्देश दिए थे। इस बीच इन राज्यों के मिजिट मतदाता सूची को वच्छेद एसआइआर के आधार पर मीपिंग करने का काम किया गया है। माना जा रहा है कि इससे एसआइआर के काम में आसानी आएगी। आयोग इस दौरान सभी राज्यों में एसआइआर का काम शुरू करने वाला है, उसमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा,

एनसीईआरटी जल्द ही पीजी और डाक्टर कार्यक्रम शुरू करेगा

नई दिल्ली, एनएसडी: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) शिक्षा में स्नातकोत्तर (एनसीईआरटी) और डाक्टर अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए समयसमय नहीं बताए। यह कर्म शिक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय के रूप में विशिष्ट श्रेणी के तहत घोषित करने के कुछ हफ्ते बाद आया है, जिससे संस्थान को अपने स्वयं के स्नातक, स्नातकोत्तर व डाक्टर डिग्री प्रदान करने की अनुमति मिली है, जो टीएर एजुकेशन व स्कूल एजुकेशन रिस्त्रिक्ट पर केंद्रित है। नए जे के साथ, एनसीईआरटी अपने स्वयं के पाठ्यक्रम को डिजाइन करने, मानकों को तय करने और डिग्री प्रदान करने में सक्षम होगा।

अक्सर ही कहा, मानित विश्वविद्यालय का दर्जा एनसीईआरटी के राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम विकास से योगदान को मान्य देने के लिए विशिष्ट श्रेणी के तहत दिया गया है। यह दर्जा एनसीईआरटी के छह क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी लागू होगा। इन कार्यों का फोकस मुख्य रूप से टीएर एजुकेशन, परिक्रमण स्टेडिज और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर होगा।



प्रतीकात्मक

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना व उत्तरखण्ड शामिल हैं। आयोग ने इन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एसआइआर शुरू होने से पूर्व जरूरी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि आयोग अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्यों में एसआइआर का काम पूरा कर चुका है। साथ ही एसआइआर के बाद तैयार हुई नई मतदाता सूची के आधार पर बिहार सहित छह राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करा चुका है।

हिमाचल में वित्तीय संकट से उबरने को लाटरी शुरू करने की तैयारी

राज्य ब्यू, जगमोहन • हिमाचल

वित्तीय संकट से उबरने के लिए हिमाचल प्रदेश में 27 वक पुनः लाटरी शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आनंदनाथ लाटरी के लिए साफ्टवेयर तैयार किया गया है। 31 मई 2025 को मीनिंगडल की बैठक में वित्तीय संकट से उबरने और बढ़ते हुए बजट को कम करने के उद्देश्य से लाटरी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया था।



हर्षजन चौधरी

लाटरी की शुरूआत स्थानीय विकास मंत्रालय की आदर्श आधार सहिता के कारण अटक की। आचार सहिता हटाने के बाद ही इसकी ऑनलाइन लाइंगिंग की जाएगी। लाटरी संचालन को पारदर्शी बनाने के लिए तैयार साफ्टवेयर से संबंधित टिकट, ब्रा प्रिन्टिंग और भुगतान प्रणाली को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि अंतर्निहितता को गंजाइश न हो। सरकार को उम्मीद है कि लाटरी शुरू होने से अक्सर, जो चिन्ता स्थानीय पर उभरना रहेगी। हिमाचल पर इस समय 1,10,500 करोड़ रुपये का ऋण है।

पीएम-कुसुम 2.0 योजना जल्द होगी लांच, किसानों को मिलेगी दोहरी आय

जागण ब्यू, नई दिल्ली

केंद्र सरकार पीएम-कुसुम योजना के नए संस्करण पीएम-कुसुम 2.0 को जल्द लांच करने की तैयारी में है। इस नई योजना से फलों व सब्जी उत्पादक किसानों को खास तौर पर फायदा होने की उम्मीद है। किसानों को दोहरी आय का मौक़ा मिलेगा क्योंकि फलदार किसानों के साथ सोलर पावर ब्रेककर मासिक कर्माई भी कर संकेतों। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा (एनएलएनई) मंत्रालय योजना का कैबिनेट नेट तैयार कर रहा है, जिस पर अन्य मंत्रालयों से विमर्श के बाद अगले कुछ हफ्तों के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है।



प्रतीकात्मक

नई योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर फैन लगाकर 10 हजार मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य होगा। किसानों को अपनी फसलों के उपर ऊर्जा ब्रेककर पर खेतर फैला लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे खेतों को रोके बिना ही बिजली का उपयोग होगा। यह योजना फल-सब्जी बाजार वाले किसानों के लिए एकसा तौर पर फायदेदार साबित होगा।

यह बेहद सस्ती बिजली मिलेगी। इससे राय सरकारों को भी फायदा होगा क्योंकि उन पर बिजली सस्तरडी का बोझ कम होगा। नई योजना का कुल आउटलेट लगभग 50 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो मौजूदा योजना से करीब 45 प्रतिशत अधिक है। इसमें केंद्रीकृत सोलर, फोडर लेवल सोलर-जेनेशन और बेटरी स्टोरेज पर भी जोर दिया जाएगा ताकि जल में भी बिजली उत्पादन रहे। 2019 में लांच कीजाने वाली पीएम-कुसुम योजना की प्रति तिमाही प्रगति निम्न है:

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, फेब्रुअरी-ए में 10 हजार मेगावाट लक्ष्य के मुक़ाबले 1,052.95 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता ही स्थापित हो सकी है। फोडर लेवल सोलर-जेनेशन में 35.13 लाख पंपों में से 14.24 लाख सोलर-जेनेटो पोप हैं। फोडर लेवल सोलर-जेनेटो में 21.77 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया है, लेकिन लक्ष्य से काफी पीछे है। इसी के मद्देनपर पीएम-कुसुम में सुधार की तैयारी है।

बिहार की लीची पर संकट, केंद्र ने संभाला मोर्चा

जागण ब्यू, नई दिल्ली

लीची पर रिंटिंग बम कोंटाणु के हमले को विरोधियों आने के बाद सरकार पक्षान में आ गई है। विशेष कार्यलय (टास्क फोर्स) गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञों को टीम उत्तर दे गई है, जो फसल को हूई क्षति का आकलन करेगी और हफते भीतर रिंटिंग बम को लक्ष्य कर रिपोर्ट देगी। रिंटिंग बम एक तरह का कोंटाणु है, जिसके हमले से लीची को गुणवत्ता प्रभावित होता है। फसल विकसित होने से पहले रिंटिंग बम से लीची को रक्षित रखने लगते हैं। बिहार प्रमुख लीची उत्पादक राज्य है। मुजफ्फरपुर की लीची को अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लक्ष्मण में सात मई को आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों ने रिंटिंग बम से लीची को जोर दे नुकसान के बारे में बताया था। इस पर शिवराज ने टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र हाट जाते आठरा के

एनआइए के मामले में तेजी को विशेष अदालतें बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

जागण ब्यू, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अभियान के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सुझावों को विशेष अदालतों के गठन के साथ कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10 से 15 मुकदमों के लिए एक विशेष अदालत होने चाहिए, लेकिन जिन हाई कोर्टों के क्षेत्राधिकार में 15 से अधिक मुकदमे संलग्न हैं, वहां दो विशेष अदालतें को निर्देश दिया कि वह एनआइए पर, 2008 की धारा-11 के तहत विशेष अदालतें बनाने के लिए संबंधित हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से संकेत करें और उनसे सलाह माशवा करें।

वे निर्देश प्रमाण-ब्याजों सुर्वाक के गंधीर कार्यवाही को आचलन के बाद प्रमाण-ब्याज बना दिया। दरअसल, पाठ्यक सेना परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रमाण-ब्याज अपने उत्तरपुस्तिका के सर्वेक्षणकर्ता को मांग लेकर कोर्ट पहुंचें थीं। उनका याचिका को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्वका ने अपने निर्देशों का एसा किया सुनवा, जिसे सुनकर अदालत में कुछ डर के लिए सलाह छ गवा। सीजेजेड ने कहा, वह भी कभी न्यायिक अधिकारों बनाने चाहते थे। वर्ष 1984 में कानून को पढ़ाई के अंतिम वर्ष के दौरान परोक्ष पास कर ली थी। लिखित परीक्षा पास कर ली थी। उसी समय उन्होंने पूजाक एच हरिणाग हाई कोर्ट में बकालत शुरू कर दी थी। संयोग से इंटरव्यू फैलल में वही बरिख न्यायाधीश शामिल थे, जिन्होंने बकालत कर हाल ही में वे बड़े मामलों में बसने का

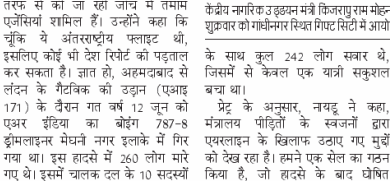
महीनेभर में आ जाएगी अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट: नायडू

गंधीनगर, अहमदाबाद: केंद्रीय नगरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नयडू ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अहमदाबाद विमान हादसे की अंतिम रिपोर्ट चवथ से चवथ महीनेभर में आ जाएगी। इस मामले की छानबीन अपने अंतिम चरण में है और पूरी परसूरीक्षा के साथ आगे बढ़ रही है।

गिफ्ट सिटी में इंडिया एयरलाइन्स लॉजिंग एंड फाहनेसिंग सॉल्यू 2.0 में हिस्सा लेने आए नयडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एयरलाइन्स एनबीईट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एनबीईटी) की तरफ से की जा रही जांच में तमाम एजेंसियाँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट थ्री, इरलायन को भी दो रिपोर्टों को पढ़ाना कर सकता है। ज्ञात हो, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक की उड़ान (एफाड 171) के दौरान गत वर्ष 12 जून को एडार इंडिया का बोइंग 787-8 इंडियाएनएन मेघन नगर उड़ान में गिर गया था। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। इसमें चालक दल के 10 सदस्य

मृतावजे व अन्य मामलों में समन्वय कर रहा है। अगर किसी की रिपोर्ट नहीं तो हम उसे पीछे छोड़ें। ज्ञात हो 30 पॉइंटों के रजनों में दो पीएम को पत्र लिखकर काकापेट बायस रिक्टर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स डाटा जारी करने की अपील की है। हमने एक साल का गठन कर रखा है, जो हादसे के बाद घोषित

रिपोर्ट 6.63 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र वाले साधो-जान द्वीप को भी इसके विरासत मूल्य और पर्यटन के प्रति संबेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'एनडीजेड' घोषित किया है। जस्ता अतिरिचयन को तारिख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर भारत के मुख्य नगर योजनाकर को अपने आभ्यन्तरी और सुझाव भेज सकती है। नगर एवं ग्रामीण योजना बोर्ड ने उद्दिगण एवं पर्यटन के प्रांति संबेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'एनडीजेड' घोषित किया है। जस्ता अतिरिचयन को तारिख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर भारत के मुख्य नगर योजनाकर को अपने आभ्यन्तरी और सुझाव भेज सकती है। नगर एवं ग्रामीण योजना बोर्ड ने उद्दिगण एवं पर्यटन के प्रांति संबेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'एनडीजेड' घोषित किया है। जस्ता अतिरिचयन को तारिख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर भारत के मुख्य नगर योजनाकर को अपने आभ्यन्तरी और सुझाव भेज सकती है।



केंद्रीय नगरिक उड्डयन मंत्री फिजजगु राम मोहन नयडू और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को गंधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए। (ए.ए.ए.)

सुआवजे व अन्य मामलों में समन्वय कर रहा है। अगर किसी की रिपोर्ट नहीं तो हम उसे पीछे छोड़ें। ज्ञात हो 30 पॉइंटों के रजनों में दो पीएम को पत्र लिखकर काकापेट बायस रिक्टर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स डाटा जारी करने की अपील की है। हमने एक साल का गठन कर रखा है, जो हादसे के बाद घोषित

रिपोर्ट 6.63 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र वाले साधो-जान द्वीप को भी इसके विरासत मूल्य और पर्यटन के प्रति संबेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'एनडीजेड' घोषित किया है। जस्ता अतिरिचयन को तारिख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर भारत के मुख्य नगर योजनाकर को अपने आभ्यन्तरी और सुझाव भेज सकती है। नगर एवं ग्रामीण योजना बोर्ड ने उद्दिगण एवं पर्यटन के प्रांति संबेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'एनडीजेड' घोषित किया है। जस्ता अतिरिचयन को तारिख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर भारत के मुख्य नगर योजनाकर को अपने आभ्यन्तरी और सुझाव भेज सकती है। नगर एवं ग्रामीण योजना बोर्ड ने उद्दिगण एवं पर्यटन के प्रांति संबेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'एनडीजेड' घोषित किया है। जस्ता अतिरिचयन को तारिख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर भारत के मुख्य नगर योजनाकर को अपने आभ्यन्तरी और सुझाव भेज सकती है।

भाबुक और प्रेरणादायक पल

न्यायिक अधिकारी बनने के सपने पर मिली थी झिड़की, आज वही बने देश के मुख्य न्यायाधीश, रंघेव्याएन मांगे ने पंडेव्याएन की याचिका खारिज, लैकिन चौफ जटिरस की कहानी ने दी प्रेरणा

जब सीजेआइ ने कोर्ट में खोला टूट सपनों का राज

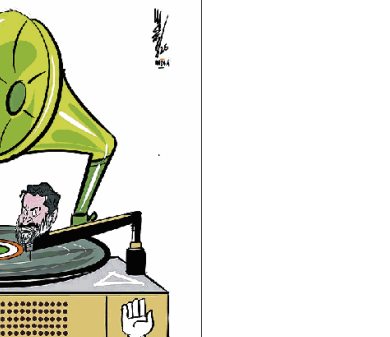
नई दिल्ली, 9 मई: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक ऐसा पल आया, जिसने अदालत की गंधीर कार्यवाही को आचलन के बाद प्रमाण-ब्याज बना दिया। दरअसल, पाठ्यक सेना परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रमाण-ब्याज अपने उत्तरपुस्तिका के सर्वेक्षणकर्ता को मांग लेकर कोर्ट पहुंचें थीं। उनका याचिका को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्वका ने अपने निर्देशों का एसा किया सुनवा, जिसे सुनकर अदालत में कुछ डर के लिए सलाह छ गवा। सीजेजेड ने कहा, वह भी कभी न्यायिक अधिकारों बनाने चाहते थे। वर्ष 1984 में कानून को पढ़ाई के अंतिम वर्ष के दौरान परोक्ष पास कर ली थी। लिखित परीक्षा पास कर ली थी। उसी समय उन्होंने पूजाक एच हरिणाग हाई कोर्ट में बकालत शुरू कर दी थी। संयोग से इंटरव्यू फैलल में वही बरिख न्यायाधीश शामिल थे, जिन्होंने बकालत कर हाल ही में वे बड़े मामलों में बसने का

अमित शाह लू, वाद से निपटने की तैयारी

की करेंगे समीक्षा

नई दिल्ली, 9 मई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लू और वाद को समांजित स्थिति में निपटने के लिए देश की तैयारियों को रजिवा को व्यापक समीक्षा करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, शाह के इंडिया एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने, प्रांतिरिक्त चेतावनी प्रणालियों, संसधनों की तैयारी व उत्तर-एजेंसी समन्वय की समीक्षा के लिए उच्च स्तरिय बैठक में अध्यक्षता करेंगे, ताकि जान का कोई नुकसान नहीं होने पाए और संपति को न्यूनतम क्षति पहुंचे। बैठक के दौरान गृह मंत्री उगत तनवीक और रिचर टाडम मंत्री एनकरा को माध्यम से बाढ़ पुनर्निर्माण और प्रकृति के तारिख में प्रभावित लोगों को मजबूत करने की स्थिति का आकलन करेंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बरिख अधिकारी मौजूद रहेंगे।

कह कर रहेंगे





आजकल

चीन से संबंधित भारत की भूआर्थिक चुनौतियां

भारत की सामरिक चुनौती और एशियाई शक्ति-संतुलन के बदलते भूगोल और वैश्विक राजनीति में चीन का उभार सबसे निर्णायक घटनाओं में समझा जा रहा है। पिछले चार दशकों में चीन ने जिस गति से आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और भूराजनीतिक शक्ति अर्जित की है, उसने विश्व व्यवस्था की दिशा बदल दी है। कभी पश्चिमी पूंजी और उत्पादन का केंद्र बना चीन अब स्वयं वैश्विक शक्ति-संरचना को प्रभावित करने में सक्षम हुआ है। भारत के लिए यह परिस्थिति सामान्य पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई है। लिहाजा भारत को उसी अनुरूप रणनीति बनानी होगी

और अफ्रीकी देशों में चीनो निवेश इस नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। चीन इन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक निर्भरता को सामरिक प्रभाव में परिवर्तित कर रहा है। श्रीलंका में अरुण संकेत के बाद रंजनोत्ता बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज पर चीन को सौंपना इस माहल के वास्तविकता का उदाहरण है। भारत के लिए यह दिनांक जो विचारक असाध्य है, क्योंकि दक्षिण एशिया जैसे सम्यक् तब भारत के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं, जबकि अब चीन आर्थिक निवेश के माध्यम से इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है।

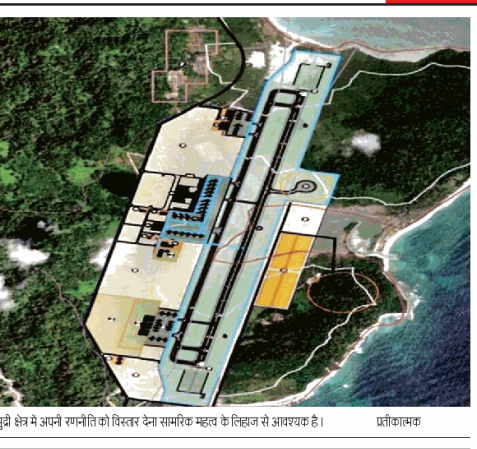
चीन की बढ़ती सैन्यता का तीसरा आयाम हिंद महासागर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, जहाँ भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्यता के तहत चीन ने भारत के चारों ओर बंदरगाह और लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित किए हैं। श्रीलंका का नवार, श्रीलंका का हंबन्टोटा, श्रीलंका का चटगाय और अंडमानी में चीन की सैन्यता के माध्यम से चीन की सैन्य और सामरिक प्रभाविताओं का पुनरावलोकन कर रहा है। इस कारण पिछले कुछ समय से भारत ने अंडमानी-निकोबार समूह को मजबूत करने, नौसैन्य आधुनिकीकरण और बंदर के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

भारत के लिए सबसे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत की परंपरिक भूमिका को कमजोर करने

की कोशिश कर रहा है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश राजनीतिक प्रभाव में बदला दिखाई दे रहा है। नेपाल में आधाभूत परियोजनाएँ, श्रीलंका में संकेत निवेश और मालदीव में अवसर-उत्पन्नकाल संयोग्य इस दिशा के प्रमाण हैं। चीन इन देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने पक्ष में रणनीतिक वातावरण तैयार कर रहा है।

चीन के उभार का एक महत्वपूर्ण पहलू मनोवैज्ञानिक और वैचारिक प्रभाव भी है। चीन स्वयं को कुशल शासन माहल के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ तेज आर्थिक विकास को लोकतांत्रिक बरस से अधिक महत्व दिया जाता है। कई विकासशील देशों में यह धारणा बन रही है कि अधिऋणकारी व्यवस्था तेजी से निर्णय लेने और बड़े आर्थिक परिवर्तन करने में सक्षम होती है। भारत के लिए यह चुनौती वैचारिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक ढांचे के साथ विकास का माहल प्रस्तुत करना चाहता है। यदि भारत आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और अवसर-उत्पन्नकाल कमजोरियों को दूर नहीं कर पाता, तो चीन का माहल कई देशों को प्रभावित दिखाई दे सकता है।

इसलिए आने वाले समय में भारत को चीन के साथ अधिक कुशलता और कोशिशता के साथ निपटना होगा। अंततः चीन का विस्तार भारत के लिए चेतनाजी भी है और अंतरिम में ही। चीनोत्तरी इस्लाम, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-संतुलन तेजी से बदल रहा है। अंतरिम इसलिए कि भारत अपने आर्थिक, तकनीकी और सामरिक ढांचे को पुनर्गठित कर सकता है।



समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीति को विस्तार देना सामरिक महत्व के लिहाज से आवश्यक है। प्रतीकचित्र

विमर्श

खरी-खरी

आदमी सड़क का

मनीष कुमार चौधरी

सड़क का आदमी सड़क का ही होता है। वह सड़क या सड़कजन्मा जैसे किसी जगह पर पैदा होता है, तब सड़क सड़क पर सड़कजन्मा जिनमें जाता है और अंततः सड़क पर ही दम तोड़ देता है। सड़क का यही आम आदमी कुछ लोगों को चुनब में लिजाता है और उन्हें खवास बनाता है। फिर वही खवास आदमी सड़क के आदमी को कभी खवास नहीं बनने देता और उसे सड़क का ही बनाए रखता है। क्योंकि वह जानता है कि वह सड़क का आदमी ही सड़क के आदमी है। सड़क का आदमी जिंदगीभर सिस्टम से लड़ता रहता है, पर सिस्टम उसे कभी भी सड़क के आदमी की औकात से ऊपर उठने नहीं देता। लेकिन वह बात उसे बहुत समय के बाद समझ में आती है।

वह जानता है कि जिस दिन वह सड़क का आदमी बनने आँका है और उठ पाएगा वह बड़े जाना है। सिस्टम यह भी जानता है कि इसी सड़क के आदमी से डरा चलोगा, इसलिए अपनी अंतिम ठककर रखने के लिए सिस्टम के आदमी को हर पल यह दिखाना चाहता है कि तु सड़क का नया, सड़क पर ही जाना है। वह उसे बारा-बारा दुःखकर कर डराना हीन बन देता है कि सचो सड़क का आदमी उसे निराला मानकर स्वीकार कर लेता है और स्थावर व चंचल-कलापी में सड़क के किसी आदमी की तरह ही व्यवहार करने लगता है। कभी कोई सड़क का आदमी खुद को सिस्टम से ऊपर समझने को पूरा न कर बैठे, इसलिए सिस्टम उसे कदम-कदम पर तुच्छता सिखाता करता रहता है।

वह जानते-सोते, सोते-हंरते, चलेते-नींदते, नींदते-उठते... अपने रोम-रोम में सड़क को बसाए रखता है और मन में यह हीलियासा होता है कि उसके भाग्य में ही सड़क का आदमी हो लिखा है, तो क्या करे। थोड़े-थोड़े सड़क सचो ही सड़क के आदमी को तरह हो जाता है। जब सचो ही सड़क वाला ही जागता तो वह सड़क से ऊपर कैसे उठेगा? इसलिए सड़क के आदमी हमेशा सड़क का होकर रह जाता है। पहले ही वह सड़क का था, अब भी सड़क का है और भूत के तम क सड़क का ही रहेगा। और सड़क के आदमी को जितने से उठे, उठकर भाग के बाद ही मिलेगा, क्योंकि सड़क के बाद सड़क के आदमी को कोई यह नहीं करता।

पोर्ट

पिछले दो बार से भाजपा मुख्यालय के नाम को चर्चा नहीं लिखा रहा। विहार के राज्यपाल काल में भी उम्मीद के मुताबिक सुबुद्ध मुख्यालय को मुख्यालय बनाया गया है।

सुबुद्ध राजन [RanjanSukesh]

राज्यपाल है कालोस के प्रमुख गठबंधन से बहर निकलने के बाद आहलाने की आशा का स्वरूप निकलने होगा है। शिवक के गठबंधन इस बात पर आज है कि कोससे तो फंसते को विधानसभा चुनाव तक बहुत तेजी से काम करेगा। क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय आदमी आकर सिलाते के कारण सरकारी कामकाज को गति बंदगी होगी। नवंबर में चुनाव परिणाम आया, उसके बाद ही अंततः बंधन विधानसभा में लगे हुए बाजपा को सरकार बनाने का अवसर मिला है।

अच्छी बात यह है कि सरकार की स्थिरता में इस समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं है। इसलिए एक मुख्यालय स्थापना उचित है यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे तेजी से काम करे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने विचार

विहार डायरी

और स्थापना के मुद्दे पर अपने प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं। सरकार को संरचना पर ध्यान दे तो यह कुछ-कुछ नीतीया कायम के वर्ष 2015-16 के निर्वाचन को तरह है। नीतीया के कार्यकाल का वह दौर है। जिसमें सरकार को कल से चुनौती नहीं मिल रही थी। नीतीया अपने पोजीशन के अनुसार सरकार चल रहे थे। आज बिहार में जो कुछ अच्छा नजर आ रहा है, उसको नीति उन्हीं वर्षों में रखी गई थी। उसके बाद के शासन में नीतीया को राजनीतिक मोर्चे पर हर कार्यकाल में कठिनाईयें उठनी पड़ीं। 2015 में जब पहाड़ों को प्रवेश बंदूक मिला था, भाजपा ने नीतीया का मध्य संबंध में उत्तराखण्ड को तय कर लिया था। 2020-22 से बीच उन्हें दो बार गठबंधन बनाया। राज्य का विकास और सरकार बनाने की चुनौती, नीतीया को इन दोनों मोर्चे पर लड़ना पड़ा था।

सरकारी कामकाज में तेजी आने की आशा

जाना है। तब के कामकाज में सुगति और लापरवाही का एक उदाहरण भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमभारती सेतु है। इसका एक स्लैब टूट कर तट में समाहित हो गया। प्रत्यक्ष रूप में यह एक घटना है। लेकिन, प्रथमपुत्र को देखें तो पाता चलता है कि इसमें तब की समस्या को बड़ा योगदान है। क्योंकि पुल की मरम्मत के लिए धन आवंटन को संघना सरकारी विभागों के बीच घुमती रही। समय पर उपचार न होने से पुल का एक हिस्सा गिर गया।

इससे पता चलता है कि तंत्र आम जनता को सुर्वाहाओं के प्रति किना संवेदनशील हो सकता है। वह पहाड़ों को किस हद तक उलगा कर रखने में सक्षम है। इससे पहले भी कई पुल टूटे हैं। उंग से खोजवनी में दो हार मामलों में तंत्र की देखी ही सुगति समने आगयी। इन वर्षों में राज्य के प्रशासनिक तंत्र में एक तरह की जड़ता बन गई है। यहाँ उपलब्ध

केंद्रीय और राज्य सेवाओं में पूरे कार्य बल का शापटी की कमी उपयोग हो पाया। परिणाम यह निकला कि अधिकारियों का एक छोटा समूह ही हमेशा सक्रिय रहा। बड़ा हिस्सा केवल नौकरों करने के लिए छोड़ दिया गया। राज्य सचिवालय में एक ही कक्षा अधिकारियों के पास प्रभाव वाले कई विभाग हैं। इन अधिकारियों की क्षमता पर प्रश्न नहीं है। मगर, वह प्रश्न तो है कि कार्य बल को पूर्ण क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रश्न ने बहुत सीमा तक तंत्र से जुड़े लोगों के मन से उत्तरदायित्व की भावना को कमजोर किया है। क्योंकि उन्हें पता है कि परिणाम के आधार पर कुछ बनने-बिगड़ने वाला नहीं है। इस स्थिति से निर्वाचित जन प्रतिनिधि आहत नहीं हैं। उनका विश्वास कर्म-कर्म विचारकों को बैठकों में सामने आता है, जब वे अपनी ही सरकार की किसी उपलब्धि

बाले तब को तथ्यों के साथ चुनौती देने लगते हैं। इसी के अलावा सरकारी भी संश्लेषण मिलता है।

नीतीया कुमार के शासन में भद्राचार को लेकर राज्य सदनशांति को नीति के पालन का एक किशय गया। मुख्यालय के रूप में सचो चौधरी भी कर रहे हैं कि भद्राचार, अपराध और सचिवालयों के मामलों में वे खूब संवेदनशीलता की नीति पर चलेते रहते हैं। जहां इस तरह से केसे इन्कार किया जा सकता है कि भद्राचार के प्रति शक्ति सह-सहायिता की नीति के बावजूद यह कम नहीं हुआ है। इसका पता उस समय चलता है कि जब कोई निर्माण पूर्ण हो किसे लोक-द्वारा को पकड़नी है तो अर्थात् बेगमि संश्लेषण को सखर खुरता है। इन वर्षों में भद्राचार कसे और कैसे रोके के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। अंतरिम में कि आने वाले दिनों में भद्राचार के मोर्चे पर शून्य सहायिता को जितनी होगी।

भारत-बांग्लादेश

आमकला तिवारी
मुर्मू बूरो प्रमुख

बांग्लादेश के विदेश विभाग ने वहां भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाघो को बुलाकर अपना विषय दर्ज कराया है। विदेश ससन ने असम से अर्ध बांग्लादेशियों को बापस भेजने की बात कही थी।

वह तो बात हुई बंगाल में सता परत की ओर। अहम अहम देते ही बांग्लादेश के उत्पत्ती बेचनी की। अब हमें ओकड़ों के जलजो में भारत और बांग्लादेश में श्यामो शांति और दोनों देशों की उन्नति को संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। 1941 को विधानसभा के अनुसार तत्कालीन पूर्वी बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 28 प्रतिशत थी। बंदरगाहे का बाद 1951 को पहली जनगणना में यह संख्या घटकर 22 प्रतिशत (लगभग 97 लाख) रह गई थी। हालांकि बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के अनुसार वहां अब 1.31 करोड़ हिंदु ही बचे हैं। दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यालय हिमांता विधान ससन के एक बयान को लेकर

आबादी की हो अदला-बदली

बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को देखते हुए भारत में रह रहे हिंदू संगठनों को भारत व बांग्लादेश की बीच हिंदू एवं मुस्लिम आबादी की अदला-बदली की मांग उठानी चाहिए

अब एक नजर डालते हैं भारत को आजादी एवं देश विभाजन के समय हुई जनसंख्या के विश्लेषण पर। वर्ष 1947 के भारत विभाजन के बाद पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के आंकड़ों के लिए 1951 की जनगणना को मुख्य स्रोत माना जाता है। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से लगभग 47 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी और पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) से लगभग 26 लाख लोग भारत आए थे। अर्थात् 1951 की भारतीय जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान के दोहरे हिस्सों से कुल 73 लाख हिंदू और सिख विस्थापित होकर भारत आए। बड़ले में भारत से लगभग 65 लाख मुस्लिम पश्चिमी पाकिस्तान और सत्त लाख पूर्वी पाकिस्तान आए।

विकास में, न सिर्फ इस्लाम ब्रह्मिक आजादी के बाद से अब तक कई बार बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो चुके जुल्मों

को देखते हुए भारत में रह रहे हिंदू संगठनों को भारत और बांग्लादेश के बीच हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या की अदला-बदली की मांग उत्पन्न-शोर से उठाने चाहिए। भारत सरकार को भी अपने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) में संशोधन करके बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में इसका समय सीमा बढ़ाने की पहल करनी चाहिए। यह बात कुछ लोगों को अताकिंक लग सकती है, लेकिन पांच अग्रस्त, 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने के बाद वहले में हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, उसे देखते हुए इस 'अताकिंक' से लगानेवाली बात को भी 'ताकिंक प्रस्ताव' में बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। अधिकांश 1903 से 1905 के बीच लाल कानन बस लागू हुए बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के बाद सूर्यनाथ बनर्जी एवं 1947 में भारत



भारत और बांग्लादेश के बीच आबादी के व्यावहारिक अदला-बदली करने पर हो विचार। फाइल



बांग्लादेश के विदेश विभाग ने वहां भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाघो को बुलाकर अपना विषय दर्ज कराया है। विदेश ससन ने असम से अर्ध बांग्लादेशियों को बापस भेजने की बात कही थी।

वह तो बात हुई बंगाल में सता परत की ओर। अहम अहम देते ही बांग्लादेश के उत्पत्ती बेचनी की। अब हमें ओकड़ों के जलजो में भारत और बांग्लादेश में श्यामो शांति और दोनों देशों की उन्नति को संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। 1941 को विधानसभा के अनुसार तत्कालीन पूर्वी बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 28 प्रतिशत थी। बंदरगाहे का बाद 1951 को पहली जनगणना में यह संख्या घटकर 22 प्रतिशत (लगभग 97 लाख) रह गई थी। हालांकि बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के अनुसार वहां अब 1.31 करोड़ हिंदु ही बचे हैं। दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यालय हिमांता विधान ससन के एक बयान को लेकर

बांग्लादेश के विदेश विभाग ने वहां भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाघो को बुलाकर अपना विषय दर्ज कराया है। विदेश ससन ने असम से अर्ध बांग्लादेशियों को बापस भेजने की बात कही थी।

वह तो बात हुई बंगाल में सता परत की ओर। अहम अहम देते ही बांग्लादेश के उत्पत्ती बेचनी की। अब हमें ओकड़ों के जलजो में भारत और बांग्लादेश में श्यामो शांति और दोनों देशों की उन्नति को संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। 1941 को विधानसभा के अनुसार तत्कालीन पूर्वी बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 28 प्रतिशत थी। बंदरगाहे का बाद 1951 को पहली जनगणना में यह संख्या घटकर 22 प्रतिशत (लगभग 97 लाख) रह गई थी। हालांकि बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के अनुसार वहां अब 1.31 करोड़ हिंदु ही बचे हैं। दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यालय हिमांता विधान ससन के एक बयान को लेकर

